MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Agreement of Nepal with China on transit rights and multiple train routes

SHRI PAVAN KUMAR VARMA (Bihar): Thank you, Sir. I hope I won't be disturbed now. Sir, I was raising an issue that in the month of March, there was a visit by the Nepalese Prime Minister, Mr. K.P. Sharma Oli, to Beijing, and, as you are aware, Sir, several agreements were signed during that visit. It is particularly relevant for us that among the agreements that were signed, there were agreements to provide multiple train routes between China and Nepal, and to grant Nepal transit rights through China. Now, obviously, Sir, this attempt to bypass the geographical interface between Nepal and India and, to some extent, the geographical dependence of Nepal on India, by these kinds of agreements between China and Nepal, has serious strategic implications for us. What surprises me, Sir, is the response of our Ministry of External Affairs, which seems to believe that because 98 per cent our trade goes through China right now, there will be no impact of these agreements and the resentments created in Nepal by the unofficial five-month blockade will have no strategic implications. I want to say to you, Sir, that even though Nepal may be at the mercy of geography, as somebody put it, it should not become the victim of diplomatic complacency. This is my point to you, and I also want to raise the question that in the light of these agreements, what are we doing in order to further strengthen our relationship with Nepal, including in areas such as greater access to ports, better border roads, easier trade and transit rights, and certainly a greater interface and interaction with the Nepalese political leadership. That is one part of it. The second part is, what China's nefarious game going on in this region is. I say this with great respect and we respect our relationship with China. Sir, you are aware that China still gives stapled visas to those from Arunachal. You are still aware that they have stalled the Maulana Masood Azhar's matter from being taken up in the U.N. And here, we have a Government that first grants a visa to a so-called Uyghur dissident, and having granted it, withdraws it. What is our relationship with China? Are we aware of what is going on between China and Nepal? And, are we aware of what is going between China and Pakistan?

So, Sir, my question to you is simply this. I think that sometimes, this Government's eye is off the strategic ball in terms of diplomacy. We saw the crisis unfold in Nepal and now, the response to the agreements that China and Nepal have signed have met with the kind of complacency rarely seen in the chancelleries of the world. Sir, through you, I urge upon this Government to respond to the fact that these agreements have been signed and they have a major impact on our strategic interest with Nepal and in the region.

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): सर, मैं माननीय सदस्य के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh) : Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

SHRI HARIVANSH (Bihar): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): सर, मैं माननीय सदस्य के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी माननीय सदस्य के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI PREM CHAND GUPTA (Jharkhand): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

श्री राज बब्बर (उत्तराखंड): सर, मैं भी माननीय सदस्य के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री नरेन्द्र बुढ़निया (राजस्थान): सर, मैं भी माननीय सदस्य के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री गुलाम रसूल बलियावी (बिहार): सर, मैं भी माननीय सदस्य के उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

†شری غلام رسول بلیاوی (بہار): سر، میں بھی مانیئے سدسیئے کے اُلیکھ سے خود کو سمبدّ کرتا ہوں۔

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh) : Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka) : Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

† Transliteration in Urdu script.

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

DR. CHANDRAPAL SINGH YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Pavan Kumar Varma.

Shifting of coach manufacturing project from Kalahandi to Visakhapatnam by Railways

श्री भुपिंदर सिंह (ओडिशा): डिप्टी चेयरमैन सर, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कालाहांडी, बलांगीर और कोरापुट को एक स्पेशल रीजन आइडेंटिफाई किया है। सर, नरला पहले मेरी कांस्टीट्यूएंसी थी। वहां पर चपटाखंड गांव में पिछली सरकार ने रेलवे की एक कोच रिपेयरिंग फैक्टरी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उसके बारे में जब हमने आरटीआई से पता किया, तो उसमें बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर उसको वहां से शिफ्ट करके आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम लाया जा रहा है। इस बात को लेकर मेरे जिले कालाहांडी में एजिटेशन चल रहा है। इस मुद्दे को हमारी पार्टी बीजेडी के सभी विधायकों ने और सभी पार्टियों के सदस्यों ने भी विधान सभा में उठाया है। अभी-अभी हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी भुवनेश्वर गए थे, तो वे चीफ मिनिस्टर से मिलने गए। माननीय नवीन पटनायाक जी ने भी इस मुद्दे को उनके सामने रखा। तो उन्होंने अभी कहा है कि वहां डेढ़ महीने के अन्दर हम इसके लिए कुछ न कुछ करेंगे, एक कमेटी बिठाएंगे।

सर, बात यहां पर यह है कि हम कोई ज्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। यह एक विडम्बना है कि जो चीज़ हमें मिल रही थी, वह भी हमसे छीनी जा रही है। यहां प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया गया। यह नीति आयोग किसके लिए बनाया गया? जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो भारत सरकार ने, पिछली यूपीए सरकार ने जब उस एरिया को सबसे पिछड़ा इलाका माना, तो वहां रेलवे का एक छोटा सा rapair wagon मैन्युफैक्चरिंग युनिट आना था। क्या यह बात सच है कि 25 फरवरी, 2014 को वहां रेलवे मिनिस्टर ऑफ स्टेट द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा जाना था? इसमें कहां तक सच्चाई है? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी जानने की उम्मीद रखता हूं। यहां पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस बात को थोड़ा गहराई से लें। रीजनल इम्बैलेंस की बात आज सारे हिन्दुस्तान में राज्यों के बीच हो रही है, लेकिन राज्यों के बीच इम्बैलेंस की बात करना तो दूर की बात है, यहां केन्द्र से भी अगर रीजनल इम्बैलेंस होता है, तो हमारी सरकार को, हम लोगों को केन्द्र नेग्लेक्ट करता है। वहां हमारे मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने और हमारी पार्टी बीजेडी के सभी विधायकों ने इस बात को बार-बार बोला है कि केन्द्र सरकार हमें नेग्लेक्ट कर रही है। हम कोई और बात नहीं उठा रहे हैं, हम false propaganda नहीं कर रहे हैं। हम issue base के ऊपर बोलते हैं कि जो चीज़ हमें मिली हुई है, उसको क्यों हमसे छीना जा रहा है? ...**(समय की घंटी)**... तो केन्द्र सरकार की तरफ से ओडिशा के लिए इसमें बड़ा नेग्लेक्ट और क्या हो सकता है? ...**(व्यवधान)**...